भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3245

दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
अमेरिकी टैरिफ नीति का भारत पर प्रभाव

3245 श्री रामजी लाल सुमन:
क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमेरिकी सरकार द्वारा भारत की वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की नीति के संबंध भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत पर अमेरिकी टैरिफ नीति के वास्तविक प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): वर्तमान तिथि तक, अमेरीका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ सहित कोई देश- विशिष्ट टैरिफ अधिरोपित नहीं किया गया है। अमेरिका द्वारा सभी देशों से इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर बिना किसी छूट के अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इन शुल्कों, जो मौजूदा ऐसे अतिरिक्त शुल्कों की तुलना में वृद्धि है, के प्रभाव का इस तथ्य के कारण गहनतापूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख निर्यातक देशों को पहले दी गई छूटों की तुलना में कोई छूट नहीं दी गई है।

भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ निरंतर नियोजित हैं। दोनों देशों ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। महत्वाकांक्षी "मिशन 500" के तहत, दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत व्यापार को दोगुना से अधिक करके 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, जिसे कई क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों को गहरा करके हासिल किया जा सकता है। दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी,बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए प्रतिबद्धता है, जिसके तहत दोनों देश बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने और प्रमुख व्यापार मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

*****